जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600 | वर्ष: 17 | संख्या: 335 | प्रभात | हिण्डौन सिटी, बुधवार 8 अक्टूबर, 2025 | पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी

यह बैठक बिहार के प्रथम चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की गई है

- राहुल व खड़गे ज़ूम के मार्फत बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि विदित है, राहुल बीस दिन की साउथ अमेरिका की यात्रा पर गये हैं और नौ अक्टूबर को ही लौटेंगे। पर, थोड़ी अटपटी बात यह है कि महागठबंधन अभी तक यह भी निश्चित नहीं कर पाया है कि उसकी घटक पार्टियों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा।
- अपुष्ट समाचारों के अनुसार कांग्रेस 50-55 सीटों पर ही उम्मीदवार खड़ा करेगी। यह संख्या गत चुनावों की संख्या से कम है। विचारणीय बात यह है कि बिहार के चुनावों में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए अतिआवश्यक है। इस अवसर पर राहुल गांधी ने साउथ अमेरिका की यात्रा का प्रोग्राम क्यों बनाया। दूसरी ओर भाजपा ने दिवाली के अवसर पर चुनाव के मध्य पैसा, शराब आदि वितरित करने का कार्यक्रम तय कर लिया है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति (सैन्ट्रल इलैक्शन कमेटी-सीईसी) की मीटिंग कल आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों मौजूद नहीं होंगे।

राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण अमेरिका के 20 दिन के दौरे पर हैं और वे 9 अक्टूबर को ही दिल्ली लौटने वाले हैं। जो नेता बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए यह बैठक ज़ूम पर आयोजित की जाएगी।

लेकिन असली समस्या यह है कि महागठबंधन अब तक यह तय नहीं कर पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह मुद्दा अभी पूरी तरह खुला हुआ है।

कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या 50 से 55 के बीच मानी जा रही है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ी गई सीटों से कम है।

महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी इतने अहम बिहार चुनावों पर ध्यान एवं समय देने के बजाय, दक्षिण अमेरिका के दौरे पर क्यों गये, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस चुनाव को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं।

इसके साथ ही, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रुप में तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है कि इंडिया ब्लॉक मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर फैसला एक बैठक के बाद सामूहिक रूप से करेगा।

विपक्ष के सामने मुश्किलों का अम्बार है, जबकि भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, और चर्चा है कि वह दीवाली से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर धन और शराब बांट सकती है और इधर, विपक्ष अब तक सीट बंटवारे को ही अंतिम रूप नहीं दे पाया है, जिससे चुनावी मुकाबले में उसकी स्थिति कमजोर होती दिख रही है।

तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। जॉन क्लार्क, मिशेल माइकल डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को क्वांटम मैकेनिक्स में खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसकी घोषणा की है।

- जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट तथा जॉन मार्टिनिस को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स की खोज के लिये दिया गया है।

भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के जॉन क्लार्क, येल यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के मिशेल एच. डेवोरेट और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के जॉन एम. मार्टिनिस को प्रदान किया जाएगा।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने "इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज" के लिए उनके अग्रणी कार्य को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राजनीति में मेरा महत्व उतना ही है जितना सब्जी में नमक'

पासवान ने गर्व से कहा, हर चुनाव क्षेत्र में मेरे बीस-पच्चीस हज़ार वोट हैं, जिन्हें मैं अपनी इच्छानुसार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में डलवा सकता हूँ

- भाजपा का मानना है कि पासवान मोदी भक्त हैं और मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और उनकी गर्वोक्ति केवल भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि विदित ही है, पासवान चालीस टिकट मांग रहे हैं और भाजपा बीस-पच्चीस देने को राजी है। पासवान समर्थकों का दावा है कि पासवान किसी भी पार्टी का साथ दे सकते हैं जो उनको मुख्यमंत्री पद के करीब लाने में काम आ सकती है और इसीलिये पासवान और प्रशांत किशोर एक हो सकते हैं, यह भी चर्चा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7, अक्टूबर। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठबंधन बनना संभव है, क्योंकि राजनीति में "दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं।"

चिराग पासवान और चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के साथ आने की चर्चा सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच चल रही बातचीत के बीच सामने आई है।

सूत्रों के मुताबिक, पासवान बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें चाहते हैं। उनका यह दावा पिछले साल लोकसभा चुनाव में 100 प्रतिशत सफलता (5 में से 5 सीटें जीतने) पर आधारित है, जबकि भाजपा उन्हें सिर्फ 25 सीटें देने के पक्ष में है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बिहार की मुख्यधारा राजनीति में दोनों ही विकल्प अप्रत्याशित हैं। हालांकि, एलजेपी को इससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका तो मिल सकता है, लेकिन किसी नए उम्मीदवार (प्रशांत किशोर) से गठबंधन करना पासवान की मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा में शायद ज़्यादा मददगार नहीं होगा।

हालाँकि, एलजेपी को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की चर्चा भर से ही भाजपा पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाया जा सकेगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि एलजेपी "सम्मानजनक सीटें" पाने पर अड़ी हुई है।

पासवान ने यह भी कहा था, "मैं सार्वजनिक रूप से इन बातों का खुलासा नहीं करना चाहूँगा, यह गठबंधन की नैतिकता के ख़िलाफ़ होगा, यह बताते हुए कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से सीट-बंटवारे की औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है।

भारतीय राजनीति के रंगमंच पर पासवान ने अपने सहयोगियों को एक अप्रत्यक्ष चेतावनी भी दी, "मैं सब्ज़ी पर नमक की तरह हूँ... मैं हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हज़ार वोट प्रभावित कर सकता हूँ।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि "मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरे पास बाहर निकलने का विकल्प हमेशा खुला है।"

भाजपा ने इस "चेतावनी" को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि पासवान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वफ़ादार सहयोगी हैं, और उनका यह बयान एलजेपी के भीतर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जीतन राम मांझी की पार्टी के कई प्रमुख नेता प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हुए

आरजेडी के प्रमुख मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी व जदयू के दो बड़े नेता भी प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए, यही रास्ता कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी चुना

- दोनों बड़े प्रमुख गठबंधन, एनडीए व इंडिया गठबंधन, पहली बार चिंतित हैं कि प्रशांत किशोर क्या वाकई में बिहार चुनाव को त्रिकोणात्मक बना देंगे।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों का नतीजा अब इस सवाल पर निर्भर करता दिख रहा है कि जन सुराज पार्टी (जेएसयूपीए) के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगे या नहीं।

भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एनडीए नेताओं पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर काफी बड़ा अभियान चलाने के बाद, अब प्रशांत किशोर वास्तविक राजनीति के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी "हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)" को बड़ा झटका देते हुए, उस पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया। इनमें मांझी की पार्टी के अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर मांझी, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. शशि यादव, प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी, प्रदेश युवा सचिव राकेश कुमार सिंह और गया जिला परिषद सदस्य पार्वती देवी शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने आरजेडी के, हाशिए पर पड़े वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी मुलाकात की, जिससे अटकलें लगने लगीं कि वे जन सुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं और संभव है कि उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जाए।

पिछले महीने जेडीयू के दो नेता, दसई चौधरी और भुवन पटेल, भी जन सुराज पार्टी में शामिल हुए थे। दसई चौधरी पूर्व मंत्री और सांसद हैं, जबकि भुवन पटेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं और जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह भी इस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं।

चुनाव के मौसम में नेताओं का दल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मानवाधिकार आयोग ने ट्रोमा सैन्टर अग्निकांड का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 7 अक्टूबर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में हुए अग्निकांड से आठ मरीजों की मौत सहित, बालकों को खांसी का सिरप देने

- आयोग ने बालकों को अमानक कफ सिरप देने तथा मृत बालक की आँख निकालने के मामले में भी अधिकारियों से जवाब मांगा।

और मृत बालक की आंख निकालने के मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। वहीं, आयोग ने इन सभी घटनाओं पर एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक व प्राचार्य सहित, राज्य के मुख्य चिकित्सा सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर पुलिस कमिश्नर और सीएमएचओ प्रथम व द्वितीय से जवाब देने के लिए कहा है। आयोग ने इन्हें कहा है कि वे इन सभी घटनाओं की बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट पेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुझे न लोभ है न पश्चाताप, मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना से'

'मुख्य न्यायाधीश उच्चतम संवैधानिक आसन पर विराजते हैं, उनका हिंदू धर्म पर हल्की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता'

- निष्कासित अधिवक्ता राकेश किशोर 2009 से दिल्ली की बार काउंसिल के सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन के भी पुराने सदस्य हैं। उन्होंने ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा उनके कृत्य के विरोध में प्रोटेस्ट आयोजित करने के बारे में कहा कि केवल सात वकीलों ने इसमें भाग लिया था, इससे यह साबित होता है कि अधिकांश वकील मेरे कृत्य के समर्थन में हैं।

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना के एक दिन बाद, निलंबित वकील राकेश किशोर ने अपने इस कदम पर कोई पछतावा नहीं जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें "कोई अफसोस नहीं" है और यह कदम सीजेआई की उन टिप्पणियों के प्रतिक्रियास्वरुप था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े एक केस में की थीं।

राकेश ने कहा, "16 सितंबर को सीजेआई की अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सीजेआई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, "जाओ, मूर्ति से कहो कि वह खुद अपना सिर जोड़ ले।" उन्होंने कहा, "जब भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई प्रकरण आता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आदेश देता है। याचिकाकर्ता को राहत मत दो, लेकिन उसका मजाक तो मत उड़ाओ... मुझे बहुत ठेस पहुंची थी।" उन्होंने मीडिया से कहा कि ऐसे कई और भी मुद्दे हैं, जिनसे वे आहत हैं।

उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर दोहराया, "मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है, "हमारे भगवान और हिंदू धर्म का मजाक मत उड़ाइए। मैं आहत हुआ था। मैं नशे में नहीं था, यह उनकी क्रिया पर मेरी प्रतिक्रिया थी। मुझे डर नहीं है और न ही मुझे अपने किये का कोई पछतावा है।"

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अनुसूचित जाति से आने वाले सीजेआई गवई को क्यों निशाना बनाया, तो किशोर ने कहा, "मेरा नाम डॉ. राकेश किशोर है, क्या कोई बता सकता है कि मेरी जाति क्या है? हो सकता है कि मैं दलित हूं। यह एकतरफा बात है कि आप उनका (सीजेआई गवई का) बचाव इस आधार पर कर रहे हैं कि वे दलित हैं।" किशोर ने जोर देते हुये कहा कि सीजेआई दलित नहीं है। उन्होंने कहा, "वे पहले सनातनी हिंदू थे, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तो वे दलित कैसे रहे? यह सोच का सवाल है।"

अपने कदम के असर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में किशोर ने कहा, "जजों को अपनी संवेदनशीलता पर काम करना चाहिए। लाखों मामले लंबित हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, और न अफसोस व्यक्त करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने मुझसे यह करवाया।"

उन्होंने आगे कहा, "सीजेआई को सोचना चाहिए कि जब वे इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो 'माइलॉर्ड' शब्द की गरिमा को समझें और उसे बनाए रखें। आप मॉरीशस जाकर कहते हैं कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। मैं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर-अजमेर हाईवे पर सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग

जयपुर, 07 अक्टूबर। जयपुर-अजमेर हाईवे पर दूदू क्षेत्र के सावरदा पुलिया के पास भीषण हादसा हो गया, जहां गैस सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। यह दुर्घटना मंगलवार देर रात हुई जब एक ट्रेलर ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद ट्रक में आग लग गई और

- हादसे में 7 वाहन आग की चपेट में आ गये और कई राहगीर घायल हो गये।

सिलेंडर फटना शुरू हो गए। धमाकों की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दीं और 200 मीटर तक सिलेंडर उछलते नजर आए। इस हादसे में 7 वाहन आग की चपेट में आ गये, और कई राहगीर घायल हो गये।

तेज धमाकों के चलते हाईवे के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्लूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा रैयर अर्थ खनिजों का अमेरिका से अनुबंध करना अभिशाप बनेगा या वरदान पाकिस्तान के लिए

भय यह है कि केवल खनिज सप्लाई करके पाकिस्तान एक रिसोर्स सप्लायर कॉलोनी बनकर तो नहीं रह जाएगा

- क्योंकि धनाढ्य देश गरीब देशों के खनिज खरीदकर समृद्धि का स्वप्न तो दिखाते हैं तथा फैक्ट्रियाँ, कॉलेज टैक्नॉलजी का वादा तो करते हैं, पर वास्तव में ऐसा बहुत ही कम होता है। रिसोर्स कॉलोनी अपने खनिज तो बेच देती है जिसका लाभ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्रोसेसिंग करके उठाती हैं। हैडलाइन्स में तो समृद्धि आती है, पर, वास्तव में देश खोखला हो कर रह जाता है।

-सुकुमार साह---
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7, अक्टूबर। 21वीं सदी को ऊर्जा देने वाले खनिजों पर नियंत्रण के लिए संघर्षरत दुनिया में अब पाकिस्तान भी उतर आया है। उसने अमेरिका की कंपनी, यू.एस. स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ 500 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। कई लोग इसे पाकिस्तान की आर्थिक दशा बदलने वाला कदम बता रहे हैं। समर्थक इसे औद्योगिक पुनरुत्थान और वैश्विक प्रभाव का पासपोर्ट कह रहे हैं, लेकिन जहाँ वॉशिंगटन नई आपूर्ति लाइनों पर और इस्लामाबाद त्वरित लाभ की ओर देख रहा है, असली सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान वास्तव में नया भविष्य बना रहा है या फिर आज की वाहवाही के लिए कल के लाभ त्याग रहा है?

"रेयर अर्थ" खनिज आधुनिक तकनीक की रीढ़ हैं, ये इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन ऊर्जा टर्बाइन, स्मार्टफोन और उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए जरूरी होते हैं। इन खनिजों के खनन और रिफाइनिंग (शुद्धिकरण) पर नियंत्रण वैश्विक प्रभाव को परिभाषित करता है। चीन वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत रिफाइनिंग क्षमता पर कब्जा रखता है, और अमेरिका इस निर्भरता को घटाने के लिए नए साझेदार खोज रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे खनिजों के भंडार हैं, और इस्लामाबाद इसे अवसर के रूप में देख रहा है। लेकिन इतिहास बताता है कि जो देश कच्चे खनिज बेचकर समृद्धि के सपने देखते हैं, वे अक्सर नतीजों की तुलना में केवल सुर्खियों में ही ज्यादा अमीर बनते हैं।

विपक्षी दलों और अर्थशास्त्रियों ने पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है, इसे संसद की अनुमति के बिना किया गया गुप्त सौदा बताया है। पीटीआई प्रवक्ता शेख वक़ास अक़रम ने डॉन अखबार को बताया, "ऐसे समझौतों में राष्ट्रीय संपत्तियों को अल्पकालिक लाभ के लिए गिरवी नहीं रखना चाहिए।" आलोचकों को डर है कि अगर पाकिस्तान केवल कच्चा माल ही निर्यात करता रहा और स्थानीय रिफाइनिंग या मूल्यवर्धन सुनिश्चित नहीं किया, तो वह "संसाधन उपनिवेश" बन जाएगा, जहाँ असली मुनाफा विदेशी कंपनियों को मिलेगा।

तथापि, समर्थकों का तर्क है कि इस एमओयू में स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयां (लोकल प्रोसैसिंग यूनिट्स) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टैक्नॉलजी ट्रांसफर) की योजना है, जिससे पाकिस्तान आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह समझौता पाकिस्तान को वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम स्थान दिला सकता है और भविष्य में अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित कर सकता है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल कागज़ पर लिखे वादों से कुछ नहीं होता, जब तक उनमें पारदर्शिता और लागू करने की समय सीमा न हो।

अन्य देशों के अनुभव पाकिस्तान के सामने मिसाल हैं। इंडोनेशिया, जो कभी कच्चा निकल निर्यात करता था, ने 2020 में निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर विदेशी कंपनियों को अपने देश में स्मेल्टर बनाने के लिए मजबूर किया। आज वही बैटरी धातुओं का वैश्विक केन्द्र है। इसके विपरीत, कांगो गणराज्य विशाल कोबाल्ट भंडार के बावजूद, गरीबी में फंसा हुआ है, क्योंकि मुनाफा विदेशी रिफाइनरों के पास जाता है। पाकिस्तान के सामने भी यही विकल्प है, इंडोनेशिया की तरह औद्योगिक संप्रभुता का रास्ता अपनाए या कांगो की तरह दोहन के चक्र में फंस जाए।

सस्टेनेबल डवलपमैंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एसडीपीआई) के अर्थशास्त्रियों का कहना है, "टैरिफ और नीतिगत प्रोत्साहन तभी कारगर होंगे, जब वे घरेलू क्षमता निर्माण से जुड़े हों; वरना पाकिस्तान अपने स्ट्रैटेजिक मिनरल्स पर नियंत्रण खो देगा।" अंतरराष्ट्रीय अध्ययन भी बताते हैं और चेतावनी देते हैं कि जो देश केवल खनन तक सीमित रहते हैं, वे कभी रिफाइनिंग या इनोवेशन में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल नहीं कर पाते, जबकि असली मूल्य वहीं पैदा होता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अलवर बालिका गृह की अव्यवस्थाओं पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

जयपुर, 7 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर बालिका गृह की अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में बाल अधिकारिता निदेशक को तलब करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में बालिका गृह की बालिकाओं की ओर से

- बालिका गृह की बालिकाओं ने गत दिनों हाई कोर्ट को शिकायती पत्र भेजा था।

भेजे एक पत्र पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान एएजी मनोज शर्मा ने कहा कि संबंधित बालिका गृह को राज्य सरकार साल 2022 तक अनुदान देती थी, लेकिन उसके बाद अनियमितताओं के चलते इसे बंद कर दिया। वहीं, बालिका गृह के संचालक ने ही मिलीभगत कर छात्राओं से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)